राम काला बनाम कार्यकारी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, करनाल, और अन्य (न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन)

दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति *प्रेम चंद जैन* के समक्ष

राम काला, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

कार्यकारी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, करनाल, और अन्य, - *उत्तरदाता*

1968 की दीवानी रिट संख्या 704

20 फ़रवरी 1970

*पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (*1953 का IV) - धारा 3, (पी), 6 (5) (जे), 23 *और* 82 - धारा *23* के तहत पंचायत द्वारा लगाया गया जुर्माना - *क्या धारा 3 (पी) में कर की परिभाषा के तहत आता है - इस* तरह के जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाला व्यक्ति - चाहे वह पंचायत के सरपंच या पंच के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 3 (पी) में "कर" शब्द की परिभाषा, व्याख्यात्मक और प्रतिबंधात्मक नहीं है। यह एक समावेशी परिभाषा है। 'शामिल' शब्द का उपयोग करके परिभाषा को ऐसी चीजों तक सीमित नहीं करके बढ़ाया गया है जो प्राकृतिक आयात के अनुसार दर्शाता है, लेकिन इसमें अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर, शुल्क, शुल्क, दर, टोल या अन्य शुल्क भी शामिल हैं। परिभाषा के सादे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले शब्द एक परिवार से संबंधित हैं और उनके अनुरूप अर्थ हैं। वे संकीर्ण महत्व के हैं और सकारात्मक रूप से जुर्माना या जुर्माना शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 82 के तहत शक्तियों के आधार पर कर लगाया जाता है जबकि अधिनियम की धारा 23 के तहत शक्तियों के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है। ये दोनों शक्तियां स्वतंत्र हैं। विधायिका, यदि ऐसा इरादा था, तो 'कर' शब्द की परिभाषा में 'जुर्माना और दंड' शब्दों को शामिल कर सकता था। इसलिए एक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है, वह पंचायत के सरपंच या पंच के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं है। (पैरा 9 और 12)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो विवादित आदेश और प्रतिवादी संख्या 10के चुनाव को रद्द करता है। 2. *ग्राम पंचायत, ग्राम बिंद्राना के सरपंच के कार्यालय में।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसपी गोयल।

)

उत्तरदाताओं के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के लिए एन. सी. जैन, वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन - राम काला ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यपालिका के आदेश को रद्द करते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित), प्रतिवादी संख्या 1, दिनांक 20 दिसंबर, 1967 की धारा 8 के तहत मजिस्ट्रेट (प्रेस्काब्दीबेड प्राधिकरण), जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया था (याचिका के अनुबंध 'ए' की प्रति)

2. याचिकाकर्ता ग्राम सभा, बिंद्राना, तहसील कैथल, जिला कमल का सदस्य है, और सरपंच के पद के लिए एक उम्मीदवार था, जिसके लिए वर्ष 1966 में चुनाव हुए थे। उत्तरदाता 2 से 4 ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रतिवादी नंबर 4 रघबीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह ग्राम पंचायत का पट्टेदार था और प्रतिवादी नंबर 3 का इस आधार पर कि उस पर कर बकाया था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को निर्विरोध सरपंच के पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10 बी के तहत मुख्य रूप से इस आधार पर चुनाव याचिका दायर की कि उसका और प्रतिवादी संख्या 3 का नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। निर्धारित प्राधिकारी, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिका की कोशिश की और अंततः 20 दिसंबर, 1967 के अपने आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया, जिसकी वैधता को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के वकील श्री एसपी गोयल ने निर्धारित प्राधिकारी के निष्कर्ष की शुद्धता को चुनौती नहीं दी क्योंकि यह याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र की अस्वीकृति से संबंधित है। विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रतिवादी नंबर 3 पर लगाया गया जुर्माना कर नहीं था और इस तरह उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील श्री एनसी जैन द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 का नामांकन पत्र सही तरीके से खारिज कर दिया गया था क्योंकि जिस तारीख को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, वह कर के बकाया में थे क्योंकि उन्होंने अधिनियम की धारा 23 के तहत उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 से वसूली योग्य जुर्माना कर की परिभाषा में आता है जैसा कि अधिनियम में दिया गया है जो निम्नानुसार है: –

"3 (पी) "कर" में इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर, शुल्क, शुल्क, दर, टोल या अन्य इम्पोस्ट शामिल हैं;

4. अधिनियम की धारा 6 ग्राम पंचायत के गठन और अयोग्यता ओं का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या सरपंच या पंच बने रहने से वंचित करती है। वही

अयोग्यता का प्रासंगिक खंड, जिसके साथ हम संबंधित हैं, निम्नलिखित पद में है:-

"6 (5) (जे) ने पंचायत समिति की ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर के बकाया का भुगतान नहीं किया है; या "

5. पंचायत के विशेष या सामान्य आदेश की अवज्ञा के लिए दंड अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रदान किया गया है जो निम्नानुसार है: –

"23. *पंचायत के विशेष या सामान्य आदेश की अवज्ञा के लिए दंड।*

कोई भी व्यक्ति जो दो अंतिम पूर्ववर्ती धाराओं के तहत किए गए ग्राम पंचायत के आदेश की अवज्ञा करता है, वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो पच्चीस रुपये तक हो सकता है; और यदि उल्लंघन एक निरंतर उल्लंघन है, तो एक और जुर्माना जो पहले के बाद हर दिन के लिए एक रुपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है:

बशर्ते कि आवर्ती जुर्माना पांच सौ रुपये की राशि से अधिक नहीं होगा।

6. कराधान की शक्ति धारा 82 में वर्णित है और निम्नलिखित शब्दों में है: –

"82. *कराधान की शक्ति।*

(एक) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या इस निमित्त सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए कोई ग्राम पंचायत अधिरोपित करेगी :-

(अ) एक गृह-कर जो कब्जाकरने वाले द्वारा या जहां कोई घर खाली है, मालिक द्वारा देय है:

बशर्ते कि यदि कोई घर एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए खाली रहता है, तो उसे गृह-कर के भुगतान से छूट दी जाएगी;

(आ) सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, सभा क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार (कृषि के अलावा) करने वाले व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है, बशर्ते कि इस तरह का कर किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभा क्षेत्र में नहीं लगाया गया हो;

(इ) यदि सरकार द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया है, तो सभा क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के कब्जे के साथ बिक्री, उपहार और बंधक के लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा लगाए गए शुल्क पर अधिभार के रूप में संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क उस दर पर लगेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई दो प्रतिशत से अधिक न हो। जैसा भी मामला हो, विचार की राशि, संपत्ति का मूल्य या बंधककर्ता द्वारा सुरक्षित राशि, जैसा कि लिखत में निर्धारित किया गया है;

(ई) यदि सरकार द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया है, तो कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर जिसे राज्य के विधानमंडल को लगाने की शक्ति है:

बशर्ते कि यदि ग्राम पंचायत कर, शुल्क या उपकर लगाने में विफल रहती है, तो

सरकार इसे लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है और इस तरह लगाए गए कर, शुल्क या उपकर को ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया माना जाएगा:

परन्तु सरकार किसी भी समय खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन प्राधिकार को वापस ले सकती है, जिसके बाद कर, शुल्क या उपकर लगाया जाना समाप्त हो जाएगा।

दो. ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित शुल्क लगाए जा सकते हैं :-

(१) पशु मेलों के अलावा अन्य मेलों में दुकानदारों से बाजारी;

(२) सड़कों की सफाई और सड़कों की रोशनी और स्वच्छता पर शुल्क सहित सेवा शुल्क;

(३) सभा क्षेत्र में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण के लिए शुल्क; और

(४) पानी की दर जहां ग्राम पंचायत द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है।

7. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पंचायत से संबंधित भूमि के एक टुकड़े पर जबरन कब्जा करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 उदे राम पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और जिस तारीख को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, उस तारीख को इस राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

8. पक्षकारों के वकीलों की संबंधित दलीलों पर, इस मामले में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत उदे राम, प्रतिवादी संख्या 3 पर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया जुर्माना 'कर' की परिभाषा में आता है या नहीं। यह विवादित नहीं है कि यदि उत्तर सकारात्मक है, तो यह याचिका विफल है और यदि यह नकारात्मक है तो इसे अनुमति दी जानी चाहिए। पूरे मामले और ऊपर उल्लिखित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए और यह याचिका अनुमति के योग्य है।

9. कर शब्द की परिभाषा, जिसके साथ हम चिंतित हैं, व्याख्यात्मक और प्रतिबंधात्मक नहीं है। यह एक समावेशी परिभाषा है। 'शामिल' शब्द का उपयोग करके परिभाषा को ऐसी चीजों तक सीमित नहीं करके बढ़ाया गया है जो प्राकृतिक आयात के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि इसमें अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले उपकर, शुल्क, शुल्क, दर, टोल या अन्य शुल्क भी शामिल हैं। * शब्द और वाक्यांश, खंड 41 में, पृष्ठ 116 पर, 'कर' शब्द को किसी नागरिक के व्यक्ति या संपत्ति पर मूल्यांकन की गई दर या धन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्र या राज्य के उपयोग के लिए सरकार। यह भी प्रावधान किया गया है कि कर एक कर सरकार के अधिकार द्वारा राज्य के उद्देश्य के लिए अपने नागरिकों या विषयों पर लगाया जाता है। पी रामनाथ अय्यर द्वारा संकलित और संपादित लॉ लेक्सिकन में, 1940 संस्करण, पृष्ठ 1259 पर, 'कर' शब्द को राष्ट्र या राज्य के उपयोग के लिए सरकार द्वारा किसी नागरिक के व्यक्ति या संपत्ति पर मूल्यांकन की गई दर या धन की राशि के रूप में परिभाषित

किया गया है; सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति पर विधायी शक्ति द्वारा लगाए गए बोझ या आरोप, और सरकार के समर्थन और सभी सार्वजनिक जरूरतों के लिए राज्य के प्राधिकरण द्वारा लगाए गए व्यक्तियों और संपत्ति के लागू आनुपातिक योगदान।

10. श्री एन. सी. जैन, प्रतिवादी संख्या 10 के विद्वान वकील। *2*, स्वीकार किया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत लगाया गया जुर्माना या जुर्माना ऊपर उल्लिखित 'कर' की सामान्य परिभाषा में शामिल नहीं था, न ही यह उपकर, शुल्क, शुल्क, दर या टोल की परिभाषा में आता है। वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 23 के तहत लगाया गया जुर्माना और जुर्माना "इस अधिनियम के तहत लगाए गए अन्य प्रतिबंध" शब्दों में आएगा। इस तर्क की शुद्धता का न्याय करने के लिए, शब्द की परिभाषा को देखना आवश्यक होगा। शब्दों और वाक्यांशों में, खंड 20, पृष्ठ 281 पर, 'इम्पोस्ट' शब्द को इसके व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कोई कर या श्रद्धांजलि और संपत्ति पर कर के रूप में व्यक्तियों पर कर के रूप में लागू होता है"। इसका अर्थ यह भी है कि आयातित वस्तुओं और वस्तुओं पर शुल्क। एक बड़े अर्थ में, यह कोई भी कर या अधिरोपण है। कर्तव्यों और आमूलनों का उद्देश्य कर या योगदान की हर प्रजाति को समझना था जो सामान्य शब्द "कर और उत्पाद शुल्क" के तहत शामिल नहीं था।

11. 'कर' की परिभाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जिनका अर्थ समान है और जैसा कि मैक्सवेल ने संविधियों की व्याख्या, 11 वें संस्करण में पृष्ठ 321 पर कहा है, "जब दो या दो से अधिक शब्द जो अनुरूप अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, एक साथ युग्मित होते *हैं।* समझा जाता है कि उनका उपयोग उनके आत्मीय अर्थ ों में किया जाता है। वे, जैसा कि यह था, एक-दूसरे से अपना रंग लेते हैं, अर्थात, अधिक सामान्य रूप से कम सामान्य के अनुरूप अर्थ तक सीमित है। इसी नियम की व्याख्या इस प्रकार शब्द और फरारेस, खंड 14, पृष्ठ 207 पर निम्नानुसार की गई है: –

«

"संबद्ध शब्द एक दूसरे से अपना अर्थ लेते *हैं, जिसका* दर्शन यह है कि एक संदिग्ध शब्द का अर्थ उसके साथ जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है और ऐसा सिद्धांत मैक्सिम "*एजुस्डेम गे*रनेरिस" से व्यापक है।

इस परिभाषा में उपयोग किए जाने वाले अन्य शब्द संकीर्ण महत्व के हैं और सकारात्मक रूप से जुर्माना या जुर्माना शामिल नहीं हैं। इस स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि 'अविनाश' शब्द का प्रयोग करके विधायिका का इरादा इस शब्द के दायरे को तदनुसार व्यापक बनाना था? परिभाषा के सादे पठन से मेरे विचार में, ऐसा कोई इरादा एकत्र नहीं किया जा सकता है और 'अपवित्र' शब्द का उपयोग अन्य शब्दों के साथ आत्मीय अर्थों में किया गया है। इस परिभाषा में उपयोग किए गए सभी शब्द एक परिवार से संबंधित हैं, और यह मानने का कोई औचित्य नहीं होगा कि "अधिनियम के तहत लगाए गए अन्य प्रतिबंध" शब्दों में अधिनियम की धारा 23 के तहत लगाया गया जुर्माना या जुर्माना भी शामिल है।

12. इस मामले को दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। कराधान की शक्ति अधिनियम की धारा 82 के तहत निर्धारित है और एक व्यक्ति को केवल तभी अयोग्य घोषित किया जाता है जब वह ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर के बकाया में होता है। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 82 के तहत निहित शक्ति के आधार पर कर लगाती है। जुर्माना या जुर्माना ग्राम पंचायत द्वारा धारा 23 के तहत लगाया जाता है।

अधिनियम और न्यायालय के कानून के स्थापित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, जुर्माना लगाते समय, ग्राम पंचायत न्यायिक रूप से कार्य करती है और आपराधिक कार्यों का निर्वहन करती है। अधिनियम की धारा 82 के तहत शक्तियों के आधार पर कर लगाया जाता है, जबकि अधिनियम की धारा 23 के तहत शक्तियों के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है। ये दोनों शक्तियां स्वतंत्र हैं। विधायिका, यदि ऐसा इरादा था, तो 'कर' शब्द की परिभाषा में 'जुर्माना और दंड' शब्दों को शामिल कर सकता था। इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत जुर्माना या जुर्माना कर की परिभाषा में नहीं आता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था और निर्धारित प्राधिकारी के विपरीत निष्कर्ष को कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है।

13. किसी अन्य मुद्दे का आग्रह नहीं किया गया था।

14. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस याचिका को अनुमति देता हूं, 20 दिसंबर, 1967 के निर्धारित प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश (याचिका के अनुलग्नक 'ए' की प्रति) को रद्द करता हूं, और मानता हूं कि प्रतिवादी संख्या 3 का नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, सरपंच के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 का चुनाव रद्द कर दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।